जन धन में खाता खुलवाना है

- कस्टमर : जन धन में खाता खुलवाना है
- बैंक मैनेजर : खुलवा लो
- कस्टमर : क्या ये जीरो बैलेंस में खुलता है
- बैंक मैनेजर : मन ही मन में .....साला पता है फिर भी पूछ रहा है, हाँ जी फ्री में खुलवा लो
- कस्टमर : इसमें सरकार कितना पैसा डालेगी ?
- बैंक मैनेजर - जी अभी तो कुछ पता नहीं
- कस्टमर : तो मैं ये खाता क्यों खुलवाऊँ ?
- बैंक मैनेजर : जी मत खुलवाओ
- कस्टमर : फिर भी सरकार कुछ तो देगी
- बैंक मैनेजर : आपको फ्री में एटीएम दे देंगे
- कस्टमर : जब उसमे पैसा ही नहीं होगा तो एटीएम का क्या करूँगा ?
- बैंक मैनेजर : पैसे डलवाओ भैया तुम्हारा खाता है
- कस्टमर : मेरे पास पैसा होता तो मैं पहले नहीं खुलवा लेता, तुम खाता खोल रहे हो तो तुम डालो न पैसे
- बैंक मैनेजर : अरे भाई सरकार खुलवा रही है
- कस्टमर : तो ये सरकारी बैंक नहीं है ?
- बैंक मैनेजर : अरे भाई सरकार तुम्हारा बीमा फ्री में कर रही है, पुरे एक लाख का
- कस्टमर : खुश होते हुए अच्छा तो ये एक लाख मुझे कब मिलेंगे ?
- बैंक मैनेजर : गुस्से में, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारी बीबी को मिलेंगे
- कस्टमर : अचम्भे से तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ? और मेरी बीबी से तुम्हारा क्या मतलब है ?
- बैंक मैनेजर : अरे भाई ये हम नहीं सरकार चाहती है
- कस्टमर : बीच में बात काटते हुए, तुम्हारा मतलब सरकार मुझे मारना चाहती है ?
- बैंक मैनेजर : अरे यार मुझे नहीं पता, तुमको खाता खुलवाना है या नहीं ?
- कस्टमर : नहीं पता का क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ
- बैंक मैनेजर : अरे अभी तो मुझे भी पूरी बात नहीं पता, मोदी ने कहा कि खाता खोलो तो हम खोल रहे हैं
- कस्टमर : अरे नहीं पता तो यहां क्यों बैठे हो, जन धन के पोस्टर को देखते हुए, अच्छा ये 5000 का ओवरड्राफ्ट क्या है ?
- बैंक मैनेजर : मतलब तुम अपने खाता से 5000 निकाल सकते हो
- कस्टमर : बीच में बात काटते हुए, ये हुई ना बात, ये लो आधार कार्ड, 2 फोटो और निकालो 5000
- बैंक मैनेजर : अरे यार ये तो 6 महीने बाद मिलेंगे
- कस्टमर : मतलब मेरे 5000 का इस्तेमाल 6 महीने तक तुम लोग करोगे
- बैंक मैनेजर : भैया ये रुपये ही 6 महीने बाद आएंगे
- कस्टमर : झूठ मत बोलो, पहले बोला कि कुछ नहीं मिलेगा,
- फिर कहा एटीएम मिलेगा,
- फिर बोला बीमा मिलेगा
- फिर बोलते हो 5000 रुपये मिलेंगे, फिर कहते हो कि नहीं मिलेंगे,
- तुम्हे कुछ पता भी है
- बैंक मैनेजर बेचारा रू अरे मेरे बाप कानून की कसमए
- भारत माँ की कसम,
- मैं सच कह रहा हूँ,
- मोदी जी ने अभी कुछ नहीं बताया है.....तुम चले जाओ..... खुदा की कसम.....तुम जाओ, ...मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि .....एक साथ ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक दोनों का इलाज करवा सकूँ।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 16-31 दिसम्बर 2014 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक लेख पढने को मिले। 'सी बी आई को प्रधानमंत्री चलायेगा या गोश्त व्यापारी' तथा 'सी बी आई की रफ़्तार कभी ढाल कभी तलवार' लेखों से स्पष्ट है कि सी बी आई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए कुछ विशेष दलाल अपने पसंदीदा व्यक्ति को सरकार द्वारा नियुक्त कराने का प्रयास करते रहे हैं-चाहे सरकार कांग्रेस (यूपीए) की हो अथवा मोदी सरकार (एन डी ए) की, और वे अपने हितों की सुरक्षा करने में सफल रहते हैं।

यूपीए व मोदी सरकार दोनों ही सी बी आई जैसी संस्थाओं को अपने पक्ष में तथा अपने विरोधियों को साधने तथा विपक्ष को नियन्त्रित करने में प्रयोग करते रहे हैं तथा करते हैं, जैसे पवन बंसल व अमित शाह को क्लीन चिट दिलाने का प्रयास तथा मुलायम सिंह यादव, मायावती आदि का मामला लटकाये रखना। विपक्ष सरकार पर सी बी आई के दुरूपयोग का आरोप लगाता है तथा सी बी आई को स्वायन्त संस्था बनाने पर जोर देता है। परंतु जब विपक्षी राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त हो जाती है तब यह भूमिका बदल जाती है, जैसे यूपीए सरकार व विपक्षी भाजपा तथा वर्तमान मोदी सरकार व विपक्षी कांग्रेस। इसमें कोई शक नहीं कि सी बी आई का 'इस्तेमाल' पूर्ववर्ती यूपीए सरकार व वर्तमान मोदी सरकार दोनों के ही द्वारा किया जाता है। और 'उनके द्वारा अपने विश्वसनीय व्यक्ति की ही ऐसी संस्थाओं में नियुक्त की जाती है।

लेख, 'खाप की नैया: नये खिवैया, खट्टर भैया' द्वारा खाप पंचायतों की भूमिका के संबंध में चौटाला, हुड्डा तथा खट्टर सरकार के दोगलेपन का खुलासा किया गया है। खापों को ये सभी अपने वोट बैंक के रूप में काम में लेते हैं और उनके नकारात्मक कार्यों को नज़रंदाज करते हैं। अतीत में खापों ने सकारात्मक व सुधारात्मक भूमिका निभाई थी, परंतु अब ये रूढिवादी, पुरुष प्रधान व अपने वर्ग का प्रभुत्व बनाए रखने की भूमिका अदा करती हैं। विवादों को निपटाने में इनकी भूमिका अक्सर बेहद पक्षपात पूर्ण होती हैं, विशेषकर महिलाओं व दलितों के मामलों में।

विदेशों से काला धन वापिस लाने के मुद्दे को नरेन्द्र मोदी व भाजपा ने लोकसभा चुनाव के समय पूरी तरह उछाला और विदेशों में जमा काला धन के आंकड़े भी मीडिया व भाषणों के जरिये जनता के सामने रखे, परंतु केन्द्र में सत्ता प्राप्ति के बाद मोदी व भाजपा के सुर बदल गए। मोदी ने यहां तक कह दिया कि उनको नहीं पता कि विदेशों में जमा काला धन के सही आंकड़े क्या है। अब तो भाजपा व मोदी काले धन का जिक्र तक नहीं करते।

इस सम्बन्ध में लेख 'काला धन: डाल-डाल पर यादव सिंह' तथा 'काला धन और मोदी सरकार: कहां गये वायदे ?' काफ़ी दिलचस्प व जनता की आंख खोलने वाले हैं। काला धन पनपता तो भारत में ही है। देश के अंदर के काले धन पर अंकुश लगाने व रोकथाम करने में मोदी सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह तो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। इस मामले में यूपीए व मोदी सरकार दोनों की एक जैसी नीति है।

'मोदी जी पब्लिक है सब जानती है', 'साम्प्रदायिकता की चुनौती' तथा 'बेटी बचाओ-धर्म बचाओ-अभियान-यानि साम्प्रदायिकता फैलाओ अभियान' लेखो में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व संघ परिवार (भाजपा समेत) द्वारा देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने व मोदी द्वारा इस मामले में चुप्पी साधे रखने का सटीक विश्लेषण किया गया है। मोदी ने इस अहम मुद्दे को नज़रंदाज कर संघ परिवार को साम्प्रदायिक खेल खेलने की मौन स्वीकृति दे रखी है तथा स्वयं विकास, स्वच्छता अभियान, सुशासन आदि विषयों को प्रचारित कर जनता को भ्रमित करने में लगे है।

मज़दूर मोर्चा में ई एस आई अस्पताल व ई एस आई मेडिकल कॉलेज तथा मज़दूरों की शोचनीय चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में लगातार लेख प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु यूपीए व मोदी सरकार दोनों ने ही इस मामले में उपेक्षा पूर्ण रवैया अपना रखा है।

'ई एस आई में श्रमिक रहेंगे बेहाल, निजी अस्पताल होंगे मालामाल', 'ई एस आई हैल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन' तथा 'ई एस आई का असल एजेंडा है चिकित्सा व्यापारियों को पालना' लेखों में मज़दूरों की चिकित्सा सुविधा के मामले में सरकार की श्रमिक विरोधी नीति का खुलासा किया गया है।

फ़रीदाबाद में ई एस आई मेडिकल कॉलेज के शुरू होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। एम सी आई के मानकों के अनुसार सबसे जरूरी अस्पताल बिल्डिंग तैयार नहीं है और न ही मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ़ है। स्टाफ़ की कमी व पर्याप्त चिकित्या सुविधा की कमी के मद्देनज़र मरीजों को काफ़ी संख्या में निजी अस्पतालों को रेफर किया जाता है और ई एस आई अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है।

मोदी सरकार तो पूर्व यूपीए से भी आगे बढ़कर निजी अस्पतालों को मालामाल करने में लगी है। गरीब मज़दूरों के वेतन में से पैसा काटकर भी उनको चिकित्सा सुविधाएं न देना उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोदी सरकार ने तो सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य क्षेत्र से भी अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है तथा स्वास्थ्य मद में आबंटित राशि में भी कटौती करने जा रही है। इससे आम जनता भी सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली चिकित्सा सुविधा से वंचित हो जाएगी तथा निजी चिकित्सा व्यवसायियों की चांदी हो जाएगी।

'तुकी-ब-तुर्की' स्तम्भ में उचित ही वर्णन किया गया है कि पूर्व कांग्रेसी सरकार और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं है। मोदी सरकार यूपीए सरकार की नीतियों को ही रीपैकेजिंग कर आगे बढा रही है। दोनों सरकारों की नीतियों में एक अंतर जरूर है और वह है कि मोदी अपनी नीतियों की मार्केटिंग करने में माहिर है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रशंसनीय व प्रेरणादायक हैं।

-प्रो.जुगल किशोर गुप्ता

पुलिसिया दमन के खिलाफ़ छात्र आंदोलन

पिछले माह में भारत के दो राज्यों (बंगाल हि.प्रदेश) में छात्रा से छेड़छाड़ के एवं फ़ीस वृद्धि के ख़िलाफ़ आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में व्यापक छात्रों ने राज्य सरकार, प्रशासन के खिलाफ़ आवाज उठाई। सरकार द्वारा इन छात्र आंदोलनों का लाठीचार्य एवं मुकदमे लगाकर दमन किया गया।

16 सितम्बर को जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता की छात्रा के साथ कुछ लम्पट तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गयी और छात्रा के पुरुष मित्र की पिटाई की गयी। इस घटना के खिलाफ़ छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों को सज़ा देने जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस प्रशासन ने तृणमूल कांग्रेस के गुण्डों के साथ मिलकर बर्बरतापूर्वकलाठीचार्य किया। अनेक छात्रों को जेल में डाल दिया गया। इस घटना के अगले ही दिन हज़ारों छात्रों ने पुलिसिया दमन के खिलाफ़ जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन कलकत्ता में प्रदर्शन किया। 20 सितम्बर को शहर के सामाजिक, राजनैतिक संगठनों ने मिलकर सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। पूरे शहर के लोगों से प्रदर्शन में आने का आह्वान किया गया था, प्रशासन द्वारा तमाम रोक लगाने के बावजूद 27 सितम्बर को भी प्रदर्शन किय गया।

हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कोर्सों की फ़ीसों में कई गुना वृद्धि की गयी। शिक्षा के निजीकरण की नीति के तहत वि.वि. प्रशासन कह रहा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में एवं यूजीसी के निर्देशों के तहत वि.वि. को 'आत्मनिर्भर' बनने का बढावा दिया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। हिमाचल प्रदेश वि. वि. में फ़ीस के खिलाफ़ तथाकथित वामपंथी संगठनों का नेतृत्व रहा है। इस आंदोलन का भी दमन किया गया।

इन दोनों ही आंदोलनों में छात्रों द्वारा पुलिसिया दमन का विरोध किया गया गया। आज परिसरों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप लगाताार बढ़ता जा रहा है, छात्र संघ चुनाव में तो कैम्पस पुलिस छावनियों में बदल दिये जाते हैं। परिसरों के जनवादीकरण के लिये छात्रों का आंदोलन सकारात्मक रहा है। हालांकि इसकी भी अपनी सीमाएं है।

इन आंदोलनों में नेतृत्व मुख्यत: संशोधनवादी पार्टियों के छात्र संगठनों व अन्य पूंजीवादी छात्र संगठनों के हाथ में रहा है। यह छात्र संगठन छात्रों को पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही समेटे रखने को संकल्पबद्ध हैं। चुनाव के समय यह अपनी भ्रष्ट व पूंजीपतियों की सेवा में लगी पार्टियों के वोट बैंक बढाने का काम करती है। इन छात्र संगठनों की लम्पटाई छात्रों से छुपी नहीं है। छात्रों की समस्या के एक मात्र हल क्रांतिकारी बदलाव के सामने यह पूंजीवादी छात्र संगठन एक रोड़ा बनकर खड़े हैं। जिन्हें बेनकाब करके ही छात्र समुदाय के क्रांतिकारी संघर्ष आगे बढ सकते हैं। मौजूदा छात्र आंदोलन में छात्रों की भूमिका छात्रों के उत्साह व अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ़ पूंजीवादी छात्र संगठनों द्वारा छात्रों को पूंजीवादी व्यवस्था में बांधे रखने को दिखाती है।

-दीपक, दील्ली

तुर्की-ब-तुर्की

''जम्मू-कश्मीर में हमारे सारे विकल्प खुले हैं।''

(विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमितशाह का बयान)

हमारा कहना है:-

- .दूसरे शब्दों में अमितशाह जी आप यही तो कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिये आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अन्यथा बाप-बेटे (नेशनल कांफ्रेस के फ़ारुख अब्दुल्ला व उमर अबदुल्ला)और बाप बेटी (पी डी पी के मुफ़्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ़्ती) को कल तक पानी पी-पी कर गालियां निकालने वाले आपके आका नरेन्द्र मोदी की भी सहमति क्योंकर बनी रहती ? समझौता तो आपको करना ही था। कम सीटें आने से आप थोड़ा जल्दी नंगे हो गये।
- देखा जाय तो कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्रों ने अपकी पार्टी के सामने सिवाय विपक्ष में बैठने के और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। दोनों क्षेत्रों से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। कश्मीर घाटी में तो एक उम्मीदवार को छोड़ कर बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गयी। अत: सत्ता में हिस्सेदारी के लिये आपका जबरदस्ती विकल्प ढुंढना बेशर्मी की इन्तहा ही कहा जायेगा। हालांकि कुर्सी की इस दौड़ में शर्मी क्या और बेशर्मी क्या ? इस हमाम में सभी नंगे है।
- दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। तब एक बार फ़िर आपके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तमाम जनसभाओं में घोषणा करते फिरेंगे कि कैसे भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। कैसे अन्य दलों ने कुशासन दिया है और कैसे भाजपा इसे सुशासन में बदलेगी।

जम्मू तथा कश्मीर के चुनाव प्रचार में भी यही सब कहा गया था। वहां आज आप यह बता रहे हैं कि आप किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। दिल्ली में यदि आपका बहुमत नहीं आया तब भी क्या यही दलील देकर खरीद-फ़रोख्त की जायेगी ? सभी विकल्प खुले हैं, इसका अर्थ और क्या लगाया जाय ?

- अन्त में यह और बता दीजिये कि जिस जम्मू क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया है, उसकी राय जानना भी जरूरी है या नहीं ? या आप समझते हैं कि एक बार वोट मिल गया तो जनता की परवाह करने की क्या जरूरत है ? यह मुग़ालता पहले भी जिनको था, वोटरों ने निकाल दिया। देर-सबेर आपका मुगलता निकलना भी तय है।